

पहाड़ी क्षेत्र से पलायन और जमीनी लोकतंत्र का संकट: रानीखेत के पास स्थित तल्ला बधाण गाँव पर एक केस स्टडी

डॉ० बीना जोशी (असि० प्रो०)

राजनीति विज्ञान रा० महिला महा विद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

Email- beenajoshi17@gmail.com

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड राज्य की अवधारणा के पीछे यहाँ की दुर्गम परिस्थितया व संवेदनशील हिमालय की चिंता छिपी है हिमालय की मिट्टी व जल पूरे देश के काम आता है उपभोगतावादी अविवेकपूर्ण विकासवादी दृष्टि कभी हिमालय में टिकाऊ विकास नहीं कर सकी। पहाड़ के गाँव शहर की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं पहाड़ के गाँवों को सत्त विकास से वंचित रखा जाना असमानता है शहर के पास सब कुछ सुविधाएँ हैं गाँव इन सुविधाओं से वंचित है। असुविधा ही समस्या की जड़ है। तल्ला बधाण गाँव भी सुविधाओं से वंचित है। सब कुछ चरमरा जाना तय है। पहाड़ से मैदान को ही नहीं वरन पहाड़ के गाँव से पहाड़ से शहर की ओर भी तेजी से पलायन हुआ है।

संकेत शब्द

Apples (स्विस गाँव), *एल०पी०एस०* (स्विस गाँव स्तर की राजनीतिक पार्टी), *सम्यों* (प्राकृतिक सुगंधित पौधा), *स्यूता* (चीड़ का बीज), *किलमोड़ी* (मेडिसिन पौधा)

समस्या के कारण

गाँवों का पलायन कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। उत्तराखण्ड की सरकारी मशीनरी समस्या को समझने में नाकाम रही है। शहरों के ठाट-बाट के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गाँवों के उत्पाद जुड़े हैं लेकिन विकास का लाभ गाँव को नहीं मिल पा रहा है। जाति, धर्म को पार्टियाँ मुद्दा बनाती है समस्याओं को नहीं। पिछले 25 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री बदले हैं। राजनेताओं की चिन्ता कुर्सी बचाने की है। राजनीतिक विकास व जागरूकता का आभाव तथा असुविधा के कारण प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद सरकार पहाड़ के लिये सही नीति नहीं बना पायी है। आधुनिक तकनीक से अछूते गाँव अकेलेपन व उदासीनता के शिकार हैं। राजधानी उपयुक्त जगह पर नहीं है। देहरादून की अधिकांश जनसंख्या उत्तराखण्ड की नहीं है। उनका पहाड़ के गाँवों से कोई भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक संबंध नहीं है चंद मैदानी भागों में सिमटी सरकार बंजर होते गाँवों के लिए कोई ठोस पृथक नीति नहीं बना पा रही है।

परिकल्पना

(जमीनी लोकतंत्र का संकट तल्ला बधाण गाँव में)

तल्ला बधाण गाँव अल्मोड़ा जिले के रानीखेत शहर से मात्र 05 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक संसाधन, सुन्दरता, भूमिगत जल स्रोतों के बावजूद यह गाँव आर्थिक व राजनीतिक विकास को तरस रहा

है। वह पिछले 40 वर्षों में इतनी तेजी से खाली हुआ है कि आगामी 10 या 12 वर्षों में एक या दो परिवार ही बचेंगे। अकेलापन, उदासीनता सुविधाओं का अभाव पलायित गाँव की भयावह तस्वीर पेश करता है।

40 वर्ष पूर्व गाँव के परिवारों की स्थिति

वर्ष	परिवार	जनसंख्या	व्यवसाय	सरकारी नौकरी
1985	35	180	कृषि, दुग्धउत्पादन मजदूरी	20

वर्ष 1985 में कृषि उत्पादन परिवार के भरण पोषण के लिये हो जाता था। खुमानी, आड़ू, काफल, पुलम, चुँवारी, अखरोट, माल्टा, सन्तरा, नाशपति, गढ़मेहल से पेड़ लदे रहते थे आज सूख गये हैं। रंग बिरंगे फूलों से मधुमक्खी पालन भी होता था लेकिन आज 2025–26 में स्थिति बदल गयी है।

40 वर्ष बाद गाँव के परिवारों की स्थिति

वर्ष	परिवार	जनसंख्या	व्यवसाय	सरकारी नौकरी
2025–26	15	82	कृषि, पशुपालन मजदूरी	06

पलायन का गाँव पर प्रभाव— अधिकांश गाँव के पलायित परिवार दिल्ली आदि के होटलों व अन्य स्थानों पर काम करते हुवे गाँव के सड़क किनारों की ऊपजाऊ भूमि को भूमाफियाओं को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। सरकार चाहती तो नीतियां बनाकर छोटे-छोटे उद्योग खोलकर रोजगार दे सकती थी। ग्राम प्रधान के पद पर 40 वर्षों से एक ही परिवार का बने रहना गाँव की राजनीतिक अजागरूकता व उदासीनता को प्रकट करता है। नीति निर्माण राजनीतिक सहभागिता में योगदान ना के बराबर है।

समाधान—गाँव से पलायन रोकना है तो कम जनसंख्या पर राजनीतिक व आर्थिक विकास के स्विटजरलैन्ड के मॉडल को अपनाना होगा।

तल्ला बधाण गाँव की तुलना Apples गांव से

तल्ला बधाण गाँव

वर्ष	परिवार	जनसंख्या	पलायित परिवार	भविष्या में पलायन	व्यवसाय	राजनीतिक दल	उद्यम
2025	15	82	20	05	कृषि पशुपालन मजदूरी	0	0

एपल्स स्विस गाँव की स्थिति –

वर्ष	परिवार	जनसंख्या	पलायित परिवार	भविष्या में पलायन	व्यवसाय	राजनीतिक दल	उध्यम
2025	229	1506	गाँव से बाहर नहीं वरना गाँव की ओर पलायन	नहीं	Sports Nursing Horse Riding school	Green Party and LPS party	Wood crafting embroidery

एपल्स स्विस गाँव का भूगोल अत्यधिक मुश्किल भरा है। आल्प्स व जूरा की उच्च पर्वत श्रेणियों ने इसके 22 प्रतिशत भाग को अनुपजाऊ बना दिया है आधुनिक तकनीक, राजनीतिक विकास के कारण यहां के पर्वतीय गाँव काफी विकसित है। यहां के गाँवों से पलायन नहीं हुआ है। वरना शहर से गाँव की ओर पलायन हुआ है नदियों व झीलों के कारण संचार व यातायात में काफी कठिनाई आती हैं फिर भी प्राकृतिक छोटे-छोटे उद्योगों की गुंजाइस बचती है। पर्यटन व शूक्ष्म दलों को आधुनिक तकनीक से बनाने की सरकारी नीति उन्हें संसार में उच्च स्थान प्रदान करती है। सरकार पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों को वहीं इस्तेमाल कर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर पलायन रोक सकती है। या छोटी-छोटी सरकारी जॉब दे दी जाये। प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य को गाँव के लोगों द्वारा न समझना, तकनीक का अभाव, वैश्विक बाजार की जानकारी न होना भी पलायन को प्रोत्साहित कर रहा है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय गाँवों में स्विजरलैण्ड की तरह प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव है क्योंकि जनसंख्या कम होती है। एपल्स गाँव के लोग अपना प्रशासन खुद करते हैं कलपुर्जों की छोटी-छोटी फौकट्टीयां हैं रोजगार आसानी से मिल जाता है। गाँव को सीधे पर्यटन से जोड़ा गया है गाँव के लोग एल पी एस व ग्रीन पार्टी से जुड़े हैं। खेती योग्य भूमि का चप्पा-चप्पा इस्तेमाल होता है जबकि तल्ला बधाण के बड़े-बड़े धान उगने वाली खेत बंजर पड़े हैं।

समाधान— गाँव का विकास कैसे हो ? —गाँव की मनः स्थिति में परिवर्तन लाकर प्राकृतिक संसाधनों का पता कर, लघु उद्योग प्रशिक्षण की सुविधा सरकार दे। मौनपालन, गुलाब जल, तुलसी का अर्क, तिमूर की पैकेजिंग, सरसों से धूप, आँवला केन्डी, किलमौड़ी जड़, खुबानी, पुलम, का ड्राई फ्रूट्स तैयार करना, बुरांश फूल से स्क्वेंश, लेमन ग्रास से मच्छर रोधी दवा व पुराने घराट का जीर्णोधार, उपल, खाद पैकेटिंग जिसमें प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्पाद की ऑनलाईन बिक्री की व्यवस्था भी की जा सकती है। **National Skill Development Corporation** को चाहिए की रोजगार सृजन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर इसके लिये इजराइल की जुरान तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

उद्देश्य व पद्धति —लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से गाँव वासियों को भागीदार बनाना, उनके प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार करना, मनोवैज्ञानिक बदलाव लाना शोध लेख का उद्देश्य है। तटस्थता का निर्वाह करते हुए आधुनिक राजनीतिक विकास उपागम के साथ-साथ मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सैमपलिंग के रूप में गाँव का सर्वे किया गया है।

निष्कर्ष:- उत्तराखण्ड सरकार का गाँवों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। सही नीतियां नहीं होने के कारण शराब व भूमाफियों का बोलवाला है। आध्यात्मिकता के स्रोत पहाड़ को बिकाऊ नहीं वरन् टिकाऊ बनाने की जरूरत है। हिमालय की मिट्टी व जल पूरे देश के काम आता है हिमालय आक्सीजन का भंडार है तथा जलवायु को नियंत्रित करता है। शासन प्रशासन देश को आँकड़ों में उलझाये रखती है। अब समय आ गया है कि गाँव की सुध ली जाये अन्यथा समस्याओं से निपटना नामुमकिन हो जायेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. हैन्स हुबर की How Switzerland is Governed
- 2- Dr. S.S. Negi- Uttarakhand me palayan : Samusya Aur Samadhan
- 3- Madleina Daen Hardt- Migration, Development and Social change in the Himalayas (2020)
- 4- Related Researches
5. पर्यावरणविद श्री अनिक प्रकाश जोशी का हिमालयन युनिटी मुवमेन्ट, गाँव बचाओ आन्दोलन।
- 6- New Aspects of political development, ल्यूशियन पाई
- 7-The coding-The federal government of Switzerland
8. समाचार पत्र- पत्रिकाएँ।
9. जुरान तकनीक,
10. थामस एल0 फ्रिडमैन लेख –“प्रकृति सियासत नहीं करती।”
11. सुरेश शर्मा- हिमालय विकास का मॉडल
12. Pahadka Dard:- विभिन्न हिन्दी व अंग्रेजी लेख(Ruskin Bord और शेखर पाठक के लेख)